

Newspaper Clips

August 22, 2012

Deccan Herald Nd
22-08-2012 P-8

IIT-Madras student commits suicide

CHENNAI, DHNS: The suicide by a 22-year-old girl student of the Indian Institute of Technology (IIT) -Madras at her campus hostel room on Tuesday sent shock waves across the state.

The student, Manasa, who joined the MTech Programme in chemical engineering three weeks ago, was found hanging from the ceiling fan in her hostel room this afternoon, sources in IIT-Madras told *Deccan Herald* here.

Hailing from Karim Nagar District of Andhra Pradesh, Manasa, apparently, left no suicide note, according to police sources, even as investigations by the jurisdictional Kotturpuram Police was continuing late this evening. The victim had used a 'dupatta' to hang herself, sources added. "It is extremely shocking and painful," a faculty member at IIT-Madras said. The tragedy has plunged the student community at the campus into gloom. Manasa's body has been recovered by police and kept in a Government Hospital mortuary here.

Hindustan ND 22/08/2012 p-2

आईआईटी दिल्ली ने अपने अध्ययन में पहचाने कारण

डूबती है दिल्ली क्योंकि झील-तालाबों पर कब्जा

नई दिल्ली | प्रभात कुमार

आईआईटी दिल्ली ने अपने अध्ययन में सड़कों पर पानी भरने के कारणों को पहचान लिया है। अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि तालाबों और झीलों पर अवैध कब्जे के कारण जलभराव होता है। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों के कारण भी पानी भरता है। यह रिपोर्ट ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के दौरान आईआईटी ने तैयार की है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

रिपोर्ट में आईआईटी ने कहा है कि दिल्ली को जलभराव से मुक्त करने के लिए ड्रेनेज प्रणाली बनाते समय पड़ोसी राज्यों के ड्रेनेज सिस्टम को भी ध्यान में रखना होगा। जिससे एनसीआर के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि के ड्रेनेज प्लान की कमियों का खामियाजा दिल्ली को न भुगतना पड़े।

आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और अध्ययन दल के प्रमुख ए.के. गोसाईं द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार ड्रेनेज की जमीन पर तेजी से फैलती अवैध कॉलोनियां, इस जमीन को खाली कराने और पुनर्वास की जटिल प्रक्रिया होने के कारण न तो पुरानी प्रणाली में सुधार हो पाता है और न ही नई व्यवस्था बन पाती है। दिल्ली में सीवर लाइनों से ही बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम होने से वर्तमान ड्रेनेज प्रणाली विफल है। साथ ही ड्रेनेज प्रणाली की देखरेख कई विभागों के हाथों में होना भी जलभराव का कारण है। रिपोर्ट में शहरी झील, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों पर अतिक्रमण और फार्म हाउसों का निर्माण

सड़कों पर पानी से परेशानी



बरसात के चलते मंगलवार को एंड्रयूज गंज इलाके में सड़क पर पानी भर गया। इससे काफी देर तक यहां ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही। ● जसजीत प्लाहा

समाधान के लिए सुझाव

- 1 जल क्षेत्रों, फ्लाइओवर, अंडरपास एवं इमारतों में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था पर विचार
- 2 झील और तालाबों को पुनर्जीवित करना होगा
- 3 दक्षिणी दिल्ली के पहाड़ी क्षेत्रों में पुख्ता ड्रेनेज प्रणाली

जलभराव पर निगम को फटकार

जलभराव पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। नगर निगम की लंबी अवधि की योजना की दलील पर जस्टिस संजय किशन कौल व विपिन सांघी की पीठ ने टिप्पणी की कि 'पिछले बीस वर्षों से निगम योजना बना रहा है', तत्काल समस्या से राहत के लिए आपने क्या किया है।

आईआईटी की रिपोर्ट से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार को तत्काल ड्रेनेज की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को हटाकर लोगों का पुनर्वास करना चाहिए। तब इस समस्या का निदान हो पाएगा। एस.ए. नकवी, दिल्ली जल बोर्ड के विशेषज्ञ

भी इस समस्या की मुख्य वजह बताई गई है। गोबर, औद्योगिक व घरेलू कचरा का सीधे सीवर लाइनों में बहाना और ड्रेनेज के साथ विभिन्न प्रकार की केबल व पानी की लाइनों से ड्रेनेज क्षमता कम होना जिससे जलभराव होता है। यह मामला

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार समिति ने हाईकोर्ट में दायर किया है। इसमें कहा गया है कि शहर में जरा सी देर हुई बारिश पूरी दिल्ली की रफ्तार को थामने के लिए काफी है। समिति ने कहा है कि सरकारी निकायों में तालमेल का अभाव है।

Deccan Chronicle Chennai
21-08-2012 P-5

IIT-M STUDENTS CAN PURSUE INTL MASTERS DEGREE

Chennai: Indian Institute of Technology, Madras, (IIT-M) and IPG Paris, France, have joined hands to provide M.Tech petroleum engineering students at IIT-M to visit IPGP to pursue an international masters degree of research in exploration geophysics at the end of the first year at IIT-M.

IIT-M director Prof Bhaskar Ramamurthi and Claude Jaupart, director, Institut De Physique Du, Paris, signed the memorandum of understanding recently.

Students who have completed first year M.Tech programme in petroleum engineering at IIT-M are eligible for this programme. The institute will send two to four eligible students to IPGP every year.

Selected students will get a dual masters degree from IIT-M and IPGP, France. Students will get health insurance and fellowship by IPGP during their stay in Paris. IPGP will also provide them with travel expenses.

आईआईटी के शैक्षिक सत्र देर से शुरू होने के संकेत

ज्ञानेंद्र सिंह/एसएनबी

नई दिल्ली। तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फार्मूले पर भले ही देश के सभी आईआईटी संस्थान सहमत हो गए हों लेकिन उनके संकाय सदस्यों को यह आशंका है कि आने वाला शैक्षिक सत्र पिछड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि जब एक चरण में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा होती थी तो उसकी प्रक्रिया सितम्बर में शुरू हो जाती थी और इस बार यह परीक्षा दो चरणों में होनी है, बावजूद इसके अब तक प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

आईआईटी संकाय सदस्यों का कहना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर भले ही अब कोई मुद्दा नहीं है लेकिन छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस बार दो परीक्षाएं होनी हैं। अधिकांश छात्रों के अभिभावक व कोचिंग संचालकों के मन में पहली परीक्षा की तिथि को लेकर अशंका बनी हुई है। पहली परीक्षा कब होगी और यदि पहले की तरह उसका कार्यक्रम बनेगा तो एडवांस जेईई परीक्षा कब से होगी क्योंकि अब तक जेईई की परीक्षा की प्रक्रिया सितम्बर से शुरू हो जाती थी जबकि सितम्बर का महीना शुरू होने में मात्र नौ दिन शेष हैं। इस परीक्षा में लगभग 15 लाख छात्रों के बैठने की संभावना है और

इसका नतीजा आने के बाद एडवांस जेईई के लिए पूर्व परीक्षा में कामयाब होने वाले करीब 1.5 लाख छात्र आवेदन करेंगे। यह आवेदन पत्र कब भरे जाएंगे या इस बार एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा, यह तय नहीं हुआ है। गत वर्षों तक जेईई के आवेदन पत्रों की बिक्री और भरने

► अब तक नहीं शुरू हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया

पहले का शेड्यूल

सितम्बर-	प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू
अक्टूबर-	प्रवेश फार्मों की बिक्री
नवम्बर-	फार्म भरने का कार्य
दिसम्बर-	फार्म जमा करने का कार्य
जनवरी-	प्रश्न-पत्रों का निर्धारण
फरवरी-	परीक्षा केंद्रों का निर्धारण
मार्च-	प्रवेश पत्रों का वितरण
अप्रैल-	परीक्षा शुरू
मई-	परीक्षा परिणाम घोषित
जून-	काउंसिलिंग
जुलाई-	नए सत्र की कक्षाएं शुरू

का काम सितम्बर-अक्टूबर से शुरू हो जाता था। दूसरा सवाल प्रश्न पत्र निर्धारण का है। इस बार आईआईटी संकाय सदस्यों को दूसरी परीक्षा (एडवांस जेईई) के प्रश्नपत्रों को

निर्धारित करने का दायित्व दिया गया है लेकिन यह काम वे कब से शुरू करें, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक तय नहीं किया है। पुरानी व्यवस्था में आईआईटी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्धारण जनवरी में हो जाता था क्योंकि दिसम्बर तक फार्म जमा होने के बाद उनकी छंटाई हो जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि कितने प्रश्न पत्र प्रकाशित कराने हैं।

फरवरी में परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार होती थी, मार्च में छात्रों के बीच प्रवेश-पत्रों का वितरण शुरू हो जाता था और अप्रैल में परीक्षा शुरू हो जाती थी। मई में परीक्षा परिणाम और जून में सभी आईआईटी संस्थानों में काउंसिलिंग शुरू हो जाती थी। जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाती थीं।

संकाय सदस्यों का कहना है कि हम लोग संयुक्त प्रवेश परीक्षा को इसलिए 2014 से शुरू करने पर जोर दे रहे थे ताकि छात्रों के समक्ष एक पारदर्शी स्थिति सामने आ जाती और उसी हिसाब से वे अपनी तैयारी करते। अगले वर्ष से सत्र शुरू करने के लिए यदि दो चरणों वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू कराना है तो पहली परीक्षा अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन मंत्रालय ने अभी तारीख तक तय नहीं की है। यह परीक्षा सीबीएसई को आयोजित करानी है।

Deccan Chronicle Chennai 21-08-2012 P-7

E-portal to protect whistleblower's ID

New Delhi, Aug. 20: Whistleblowers using the landmark RTI Act to blow the lid off corruption in various agencies have met with threats, some even losing their lives, but an online portal is helping such people get details they want without revealing their original identity.

The brainchild of an IIT engineer, an NRI and a web designer, the portal *RTI Anonymous* has come a long way since its inception last October.

Aimed at protecting the original identity of the person who needs information on any subject, *RTI Anonymous* community files an application with the agency concerned in their name and upload the documents obtained on their website. The original information seeker is also notified through an email. The idea of launching a platform to protect the whistleblowers' struck Ritesh Singh, an IIT-Kharagpur student, after RTI activist Shehla Masood's murder in Bhopal in August 2011.

"We did not want RTI activists to live in the shadow of fear. We thought we could leverage technology to solve this problem by acting as a facilitator. Since I was

The idea of launching a platform to protect the whistleblowers struck Ritesh, an IIT student, after RTI activist Shehla Masood's murder in Bhopal in 2011

working in the field of RTI since 2003, not much background work was required," Mr Singh said.

The trio launched the portal with an investment of a paltry ₹10,000.

Twenty-eight whistle blowers have been killed since the RTI Act has come into force and many are living in the shadow of fear, the portal said. The founders said that since its inception, the website has helped 350 whistleblowers in obtaining information without being susceptible to any kind of harassment or victimisation.

The requester just has to draft the RTI Application as much as he/she can and *RTI Anonymous* will take care of the rest, promises the online community. — PTI

Education reforms need of hour

SAM Pitroda, who for more than three decades, led several use-of-technology revolutions in India, was in Pune a few weeks ago. In his short, one-day visit, which had a busy schedule, he spent more than an hour to interact with SME entrepreneurs, who were cultivated and incubated by the science and technology park on the Pune university campus. Way back in the 1980s, he became the part of mission-driven projects initiated by Rajiv Gandhi and launched the Centre for Development of Telematics (C-DOT) that in just a few years, changed the entire way Indians used to have access to telephone communication. The access to telephone, which was a rare commodity before the 80s, soon became free and the entire nation got 'audibly connected', locally and globally. Pitroda was disconnected with the technology revolution in India for a gap of few years. He was back in the US and went into mobile communication space and started a new venture, C-Sam. Pitroda has ways been entrepreneur with a difference; a risk-taking individual, but driven with focused objectives. Hence, it was refreshing to see him communicating with young entrepreneurs on the national innovation council. His strong desire is to set up state-level innovation councils and create a \$1 billion fund for supporting new innovations, which the youth in our universities, research laboratories and industrial clusters, may be struggling with. These include change in the lifestyle of citizens in many domains that touch their lives, such as drinking water, sanitation, pollution, health, use of alternative sources of energy and so on. There is also one more change that is happening

Arun Nigavekar



Bhish Bahnerjee

CORE SUBJECTS: The real challenge is to create a legal environment that while respecting academic freedom, enables all universities to have credit-based modular structures for students to make course choices

with the advent of the National Knowledge Network (NKN). NKN is a state-of-the-art, multi-gigabit, pan-India network for providing a unified high-speed network backbone for all knowledge-related institutions in the country. The base of this mission-driven knowledge network is to touch "the very core of the country's quest for building quality institutions with requisite research facilities and creating a pool of highly trained professionals. NKN will enable scientists, researchers and students from different backgrounds and diverse geographies to work closely for advancing human development in critical and emerging areas". NKN is busy in creating massive optical fibre infrastructure connecting *panchayats, talukas* and district offices, state and central authorities, universities and research and development laboratories.

The assured broadband

connectivity to colleges and universities opens a large window of opportunity for researchers and teachers to work on education and application-relevant content in open source. Today, the Indian university system is multi-layered — central universities, state private universities, deemed-to-be universities, national institutions, open universities, and finally, state public universities. Public universities, which are around 280, carry the maximum burden of educating the students — 75 per cent of 125 million students in the eligible age group, 18 to 25 years. On the face of it, the six-layered university system looks the same, but there are enormous variations among these six layers, both at macro and micro levels, in elements that are at the core of universities, namely academic structures, subject-discipline mobility and operational autonomy. It is fine to have total internal freedom

for each of the institutions in academic curriculum and delivery and assessment methods. But, the real challenge is in the creation of a legal environment that while respecting academic freedom, makes all universities to have credit-based modular structures that encourage mobility of students for making permutations and combinations of different subjects from other disciplines and even enables students to take modules from other universities. These advantages would emerge through NKN. It would widen knowledge base and would give students advantage of earning a single degree from multi-universities. Indian universities, in a true sense, would become the centre of cultivation of youths with clarity on their achievements that they desire to reach in their life.

This would require massive reforms at policy and legal levels for cultivation of a cohesive

strategy and understanding among central and state governments. The concurrency of education at the state and central levels and variations of expectations and aspirations of states demand such a convergence. Today, we are facing dual discrepancies that hinder these reforms both at the central and state levels. The larger domain of higher and professional education is owned by people who also sit in various assemblies and in parliament. It is also involves stakeholders, such as a fairly large percentage of teachers for whom education is now a sheer economic proposition and support staff, who view their job as a tool to be a part of growing educational industry, and also, people who are on the periphery of education but are well connected with people's representatives, which gives them strength to control and manage educational institutions not for the love of it or for the benefit of society, but to achieve societal recognition and also personal financial advantage. Public universities, which are expected to give real support to poor and low-income families, are also corroded both academically and operatively. This has been perpetuating for decades and has created a very unhealthy environment that suffocates reforms in the education system in a country that is searching for new path for enhancing opportunities for the youth.

The larger question is: Who would bell the cat? Would the central government accept such a challenge?

arun.nigavekar
@mydigitalfc.com

(The writer is former
chairman of UGC, former
vice-chancellor of University
of Pune and founder
director of NAAC)

Hindustan Times ND 22/08/2012

P-7

DU's academic congress all set to revamp education

Shaswati Das

■ shaswati.das@hindustantimes.com

NEW DELHI: For the first time, Delhi University will open its doors to parents, students and schools to voice their opinion and work towards revamping higher education.

While the year has seen a spate of innovation projects, courses and programmes are taking shape, DU's Academic Congress is all set to discuss changes in the present education model.

"The Academic Congress will focus largely on re-thinking higher education. This means that higher education is to be linked with school education and community needs. We will be involving schools, parents, principals and will be looking at building interdisciplinarity in education," said Malashri Lal, dean of academic activities and projects, DU.

The Academic Congress, which will be held on September 6 and 7, will be a congregation of about 600 people — teachers, students, school principals and parents — all of who will work towards filling the chasm between various levels of education.

HOW WILL IT WORK?

- The Academic Congress, which will be held on September 6 and 7, will be a congregation of about 600 people.
- It will focus mainly on building interdisciplinarity of education
- The programme will involve schools, parents and students who will voice their opinion for revamping higher education.

"One of the main aims of the programme will be to move away from the learning by rote methodology and focus more on hands-on project work. The programme will be all about innovation and creativity," Lal added.

Students also said that such a model would stand future aspirants in good stead.

"When we apply for jobs or higher education, there is a strong disconnect between what we learn in school, in college and what we are about to be taught in future. The western model of education is very successful and some aspects of it need to be implemented in our system too," said Gaurav Verma, a former student of Kirori Mal College.